

मुंबई में 22 जुलाई, 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन — 'कल से परे बैंकिंग' विषय पर गवर्नर का 'फायर साइड चैट' सत्र (संपादित अंश)

संजीव चड्ढा, प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

गवर्नर साहब, एक बार फिर से असाधारण उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें इस बात से सचमुच संतुष्टि मिली है कि बाहरी क्षेत्र के मामले में, पड़ोसी देशों में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद भारत एक अलग और बहुत मज़बूत स्थिति में है। साथ ही, मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों पर आपने बात की कि बैंकों को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वे न केवल इस सम्मेलन के लिए, बल्कि अगले कुछ वर्षों के लिए भी कार्यसूची तय करेंगे। कुछ सवाल हैं, गवर्नर साहब; पहला मौद्रिक वातावरण पर, और फिर कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी, जिनका आपने उल्लेख किया था।

ऐसा लगता है कि अब हम 'अत्यधिक सहजता' के दौर से निकलकर, भारी अनिश्चितता या शायद भारी उतार-चढ़ाव के दौर की ओर बढ़ रहे हैं। यह उतार-चढ़ाव वस्तुओं की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति में रुकावटों, महंगाई और ब्याज़ दरों के मामले में हो सकता है। 'अत्यधिक सहजता' के समय में महंगाई को काबू में रखने की नीति ने बहुत अच्छा काम किया है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या भारी उतार-चढ़ाव के इस दौर में भी यह एक सही ढाँचा है? या फिर, क्या केंद्रीय बैंकों को थोड़े और लचीले ढाँचे का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है?

शक्तिकांत दास

मुझे लगता है कि महंगाई को काबू में करने के मामले में हमारे पास जो मौजूदा ढाँचा है, उसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। हमने 2016 में अपने देश में इस महंगाई-को लक्ष्य करने के ढाँचे को लागू किया था। अगर मुझे ठीक से याद है, तो 2016 से लेकर महामारी की शुरुआत (फरवरी 2020) तक औसत सीपीआई महंगाई (हेडलाइन महंगाई) 3.90 प्रतिशत थी; उसके बाद, हमें कोविड से एक बहुत बड़ा झटका लगा। चूंकि हमारे 4.0 प्रतिशत प्लस/माइनस 2.0 प्रतिशत के लक्ष्य में पहले से ही लचीलापन मौजूद है, इसलिए एमपीसी ने उस लचीलेपन/गुंजाइश का इस्तेमाल करके थोड़ी ज़्यादा महंगाई को बर्दाश्त करने का फैसला किया, जो 4.0 प्रतिशत से ज़्यादा थी। महंगाई-लक्ष्य करने के ढाँचे में मौजूद इसी लचीलेपन की वजह से एमपीसी और रिज़र्व बैंक नीतिगत दरों को कम कर पाए, ताकि भारी मात्रा में चलनिधि डाली जा सके और कई दूसरे उपाय किए जा सकें। ये उपाय रिज़र्व बैंक ने कोविड के हमले या असर से निपटने के लिए किए थे, जिसका असर न सिर्फ़ वित्तीय क्षेत्र पर, बल्कि असली अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। यह पूरा ढाँचा काफी अच्छा रहा है। महंगाई को लक्ष्य करना एक ऐसी चीज़ है जो हर समय ज़रूरी होती है; जैसाकि कहा जाता है और जैसा कि सबको पता है, अगर महंगाई ज़्यादा हो तो आम आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिना किसी कीमत स्थिरता ढाँचे के, महंगाई से दूसरे तरह के नतीजे भी निकल सकते हैं, जो देश की वित्तीय स्थिरता को कमज़ोर कर देंगे।

आगे चलकर, जब तक केंद्रीय बैंक को महंगाई को नियंत्रित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का काम नहीं सौंपा जाता; जब तक केंद्रीय बैंक इस काम को पूरा करने के लिए समय-समय पर नीतिगत दरों में ज़रूरी बदलाव नहीं करता, तब तक ऋणात्मक ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। यह बचत करने वालों के लिए एक बड़ी रुकावट का काम करेगा; यह वित्तीय बचत के लिए एक बड़ी रुकावट होगा। कम वित्तीय बचत का असर किसी भी देश के निवेश के परिदृश्य या पूरे निवेश के वातावरण पर पड़ेगा। अब, इसके दूसरे नतीजे भी हैं।

इसलिए, मुझे लगता है कि चूंकि हम कोविड जैसे संकट से गुज़रे हैं, और अब यूरोप में चल रहा युद्ध—जिसने एक बार फिर वास्तविक क्षेत्र में कई तरह के प्रभाव पैदा किए हैं। महंगाई का एक लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करने की कोशिश करना वित्तीय स्थिरता को पक्का करता है। न सिर्फ़ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में इसे बनाए रखा जाता है और यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की कुंजी है। जहाँ तक भारत की बात है, यह ढाँचा महामारी से पहले और महामारी के दौरान भी बहुत अच्छी तरह से काम करता रहा है। यहाँ तक कि अभी भी, मैं कहूँगा कि जो कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, उनके मामले में हम समय की ज़रूरतों के पूरी तरह अनुरूप हैं। मुझे लगता है कि यह ढाँचा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और इसे जारी रहना चाहिए। मेरी निजी राय और रिज़र्व बैंक में हम सभी की राय यह है कि हमें सिर्फ़ अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों में बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र की व्यापक ज़रूरत यही है कि ऐसा ही एक ढाँचा मौजूद रहे।

संजीव चड्ढा

धन्यवाद, गवर्नर; बस इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल और है। जहाँ लगभग सभी सेंकेंद्रीय बैंक एक साथ मिलकर अपनी नीतियों को सख्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, वहीं वे बहुत अलग-अलग स्थितियों में हैं। ईसीबी के लिए, ऐसा लगता है कि सभी विकल्प बुरे ही हैं — या तो महंगाई पर काबू पाएं या फिर संभावित सरकारी कर्ज़ के संकट का सामना करें; वहीं फेड ज़्यादा बेहतर स्थिति में लगता है, क्योंकि अमरीकी अर्थव्यवस्था की अंदरूनी गतिशीलता शायद बनी रहेगी, भले ही उसे मंदी लानी पड़े। इस संदर्भ में आप भारत को किस पायदान पर रखेंगे? क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सुधरती अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने का खतरा है, या फिर ब्याज दरों के सामान्य होने के बावजूद विकास की गति तेज़ होती रहेगी?

शक्तिकांत दास

एमपीसी के वक्तव्य, कार्यवृत्त और एमपीसी के प्रस्ताव में यह साफ़ तौर पर कहा गया है — और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्यों में उल्लेख किया है— कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी या चलनिधि से जुड़े हमारे फ़ैसले हमेशा विकास के पहलू को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। कानून कहता है कि रिज़र्व बैंक की ज़िम्मेदारी है कि वह विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखे। इसलिए, विकास के लक्ष्य को हर समय ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमने अब क्रम बदल दिया है। क्रम बदलने का मतलब है— प्राथमिकताओं का क्रम। फ़िलहाल, हमारा ध्यान महंगाई पर है, जिसके बाद विकास पर। इसलिए, चलनिधि या नीति दरों के संबंध में हम जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका विकास और आर्थिक गतिविधियों के फिर से पटरी पर लौटने पर किस तरह का असर पड़ेगा। इस साल के पहले तीन महीनों में और यहाँ तक कि जुलाई में भी अब तक, जहाँ तक भारत की बात है, उच्च-आवृत्ति वाले संकेतक (तेज़ी से बदलने वाले संकेतक) बहुत ही सकारात्मक दिख रहे हैं। चाहे आप जीएसटी वसूली देखें या

ई-वे बिल देखें— बीच में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन अब उनमें सुधार हुआ है। कुल मांग में भी सुधार हुआ है, और शहरी मांग काफी मजबूत है। ग्रामीण मांग में भी अब तेज़ी आने के संकेत दिख रहे हैं। महात्मा गांधी NREGA के तहत काम की मांग में भी अब कमी आई है। इसलिए, उच्च-आवृत्ति वाले संकेतक के कई संकेत— जैसे कि यात्री वाहनों की बिक्री और ट्रैक्टरों की बिक्री—सकारात्मक विकास की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए, हमारा नज़रिया यह है कि हम महंगाई की समस्या से सीधे तौर पर निपटें, लेकिन साथ ही विकास के लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। आखिरकार, हमारा लक्ष्य यही है— और आगे भी यही रहेगा— कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक 'सॉफ्ट लैंडिंग' (बिना किसी बड़े झटके के सुचारु बदलाव) सुनिश्चित करें। यूरोप में युद्ध छिड़ने तक हम एक तरह की 'सॉफ्ट लैंडिंग' (नरम स्थिति) तक पहुँच चुके थे। इस युद्ध ने चुनौतियों, मुद्दों और समस्याओं की एक नई जटिलता पैदा कर दी है, जो सामने आई हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। वस्तुओं की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें, और उनका हम पर पड़ रहा असर; मौद्रिक नीति में सख्ती और उसका आगे पड़ने वाला प्रभाव; पूंजी का बाहर जाना; मुद्रा का अवमूल्यन— हम इन सभी मुद्दों से निपट रहे हैं।

हमारा लक्ष्य और हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था की 'सॉफ्ट लैंडिंग' हो, जहाँ महंगाई को कुछ समय के भीतर 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब लाया जा सके। साथ ही, आर्थिक विकास की गति में जो कमी आती है, वह भी नियंत्रण योग्य सीमाओं के भीतर रहे।

संजीव चड्ढा

धन्यवाद, गवर्नर महोदय। 'सॉफ्ट लैंडिंग' का अर्थ निश्चित रूप से यही है कि मौद्रिक नीति समय के साथ किस तरह काम करती है। तो, मेरा सवाल यह है कि जहाँ ब्याज दरों का अल्पकालिक रुझान तो स्पष्ट है, वहीं इस बात को लेकर कुछ अस्पष्टता बनी हुई है कि हम ब्याज दर चक्र में इस समय किस पड़ाव पर हैं। क्या यह दरों का एक त्वरित सामान्यीकरण है, जो आगे चलकर दरों में स्थिरता में बदल जाएगा? या फिर यह महंगाई से जुड़ी उम्मीदों को नियंत्रित करने और बाहरी आर्थिक माहौल को संभालने के उद्देश्य से उठाया गया कोई कदम है?

शक्तिकांत दास

हमारा दृष्टिकोण, जैसा कि हमने पिछली एमपीसी में भी कहा था, 'निभाव' को वापस लेना है। नीतिगत दर अभी भी उस स्तर से कम है जहाँ हम महामारी से पहले थे। महामारी से पहले, हमारा नीतिगत दर 5.15 प्रतिशत थी। अब नीतिगत दर 4.90 प्रतिशत है। चलनिधि के मामले में, हम अभी भी महामारी से पहले के स्तर से नीचे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चलनिधि में काफी कमी आई है और हमने वीआरआरआर और दूसरे उपायों के माध्यम से पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे, इसलिए चलनिधि कम हो गई है। फिर भी, यह अभी भी उस स्तर से ज़्यादा है जहाँ हम महामारी की शुरुआत के समय थे। बेशक, यूरोप में युद्ध की वजह से आपके सामने नई चुनौतियाँ और नए मुद्दे खड़े हो गए हैं। हम अभी भी 'निभाव' वापस लेने के इरादे में हैं। हमारा मकसद महंगाई की उम्मीदों को स्थिर रखना है और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था?

संजीव चड्ढा

क्या मांग का प्रबंधन भी इसका एक हिस्सा है, या फिर, क्योंकि बाहरी माहौल के लिहाज़ से यह ज़्यादातर एक अस्थायी कारक है, तो क्या इस बात की संभावना है कि हम अभी जो कदम उठा रहे हैं, उन्हें बाद में वापस ले लें?

शक्तिकांत दास

जैसा कि मैंने कहा, हमारा मकसद यह है— मैं इसे संक्षेप में बताता हूँ: पहला, 'निभाव' वापस लेना; दूसरा, कदम उठाना और यह सुनिश्चित करना कि महंगाई की उम्मीदें स्थिर रहें; और तीसरा, मौद्रिक नीति के उपायों के माध्यम से मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन सुनिश्चित करना—यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए, यह मांग को बेवजह कम करने का सवाल नहीं है। यह मूल रूप से एक संतुलन बनाने का मामला है; मौद्रिक नीति की दरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मांग और आपूर्ति की स्थितियों के बीच संतुलन बना रहे।

संजीव चड्ढा

गवर्नर साहब, आपने जो बात कही, उसके आखिरी हिस्से पर बस एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे। जहाँ तक संचार और नीतिगत उपायों में 'अनुमान लगाने की क्षमता' का एक वांछित लक्ष्य होने का सवाल है, तो क्या एफओएमसी सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले 'डॉट प्लॉट' जैसा कोई तरीका आरबीआई के लिए भी एक अच्छा विचार होगा?

शक्तिकांत दास

आज की स्थिति—और पहले भी ऐसी ही रही है—बेहद अस्थिर और अनिश्चित है। ऐसे अनिश्चित समय में, 'डॉट प्लॉट' जारी करने से दोनों ही पक्षों में अनावश्यक उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। इससे ऐसी उम्मीदें जगेंगी, जिन्हें आप अपने कार्यों के ज़रिए पूरा कर भी सकते हैं और नहीं भी। फरवरी के पहले हफ़्ते में, जब हमने मौद्रिक नीति प्रस्तुत की थी; तब किसी को भी— यहाँ तक कि 19 या 20 फरवरी के आस-पास भी—इतने बड़े पैमाने पर युद्ध होने और उसके प्रभावों की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए, मान लीजिए कि अगर आपने 'डॉट प्लॉट' जैसा कुछ जारी किया होता और बहुत साफ़-साफ़ बताया होता कि हम इस तरह आगे बढ़ेंगे— जो कि हर सदस्य की सोच को दर्शाता है— तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती। इस तरह, आप अनावश्यक उम्मीदें पैदा कर देते हैं, जिन्हें आप पूरा कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए, ऐसे अनिश्चित और अस्थिर समय में, मुझे लगता है कि 'डॉट प्लॉट' वाला तरीका अपनाना एक समस्या है, क्योंकि आपको हर बार अपना रुख बदलना पड़ेगा, जबकि संवाद में कुछ हद तक एकरूपता होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि स्थिति अस्थिर है; और जब तथ्य बदलते हैं, तो मैं भी अपने कार्य बदलता हूँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि— मोटे तौर पर— हमारे दृष्टिकोण में किसी न किसी तरह की एकरूपता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका में 'डॉट प्लॉट' से जो हासिल हो रहा है, उससे ऐसी उम्मीदें पैदा होंगी, जिन पर आप शायद खरे न उतर पाएँ। वैसे भी, 'फॉरवर्ड गाइडेंस' (आगे की दिशा-निर्देश) उस मौद्रिक नीति वक्तव्य के ज़रिए दिया जाता है, जिसे हम जारी करते हैं; और हर सदस्य की व्यक्तिगत सोच तब सामने आती है, जब एमपीसी की बैठक के ठीक दो हफ़्ते बाद

कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं। इसलिए, हम यह काम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन 'डॉट प्लॉट' जारी करना और खुद को कुछ खास बिंदुओं से बाँध लेना मौजूदा समय में कारगर नहीं होगा, जब स्थिति इतनी अनिश्चित और अस्थिर है।

संजीव चड्ढा

धन्यवाद, गवर्नर महोदय। अब मैं उन कुछ क्षेत्रों पर बात करना चाहूँगा, जिनका उल्लेख आपने अपने भाषण में किया है। केंद्रीय बैंक प्रमुख संस्थाओं और गतिविधियों को विनियमित करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। जब महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियाँ— जैसे कि भुगतान, ऋण देना और अर्ध-उधार गतिविधियाँ— अविनियमित संस्थाओं की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, तब इस दायित्व को पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण है?

शक्तिकांत दास

यह एक ऐसा मुद्दा है, जिससे हम निपट रहे हैं। ऐसी बहुत सी अविनियमित और बिना लाइसेंस वाली संस्थाएँ मौजूद हैं, जो अब अलग-अलग तरह के ऋण देने का काम कर रही हैं। कुछ लाइसेंस वाली संस्थाएँ भी हैं, जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रही हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए, हम इन मुद्दों से निपट रहे हैं, और हमने एक समिति बनाई है। हमने समिति की सिफ़ारिशों की जाँच की है और हम इस संबंध में बहुत जल्द ही ज़रूरी गाइडलाइंस जारी करेंगे। इसमें हमारी शुरुआती सोच से ज़्यादा समय लगा है। लेकिन स्थिति बहुत जटिल है और हम सावधानी बरत रहे हैं। एक तरफ़, आपको नवाचार, किसी नए उत्पाद या नए तरीके का समर्थन करना होता है। दूसरी तरफ़, आपको वित्तीय स्थिरता बनाए रखनी होती है और यह देखना होता है कि कहीं कोई बेवजह का लिवरेज या जोखिम न पैदा हो जाए। इसलिए, आपको एक बहुत ही नाज़ुक संतुलन बनाना होता है और, इसीलिए, हम इस मुद्दे से बहुत सावधानी से निपट रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही हो जाएगा; हमने ज़्यादा समय इसलिए लिया है क्योंकि पूरी स्थिति बहुत जटिल है, और हम बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही संतुलित फ़ैसला लें जो नवाचार का समर्थन करे और साथ ही, किसी भी तरह से, वित्तीय स्थिरता से समझौता न करे, न ही ज़्यादा लिवरेज की स्थिति पैदा करे और न ही कोई बेवजह का वित्तीय जोखिम खड़ा करे।

संजीव चड्ढा

धन्यवाद, गवर्नर साहब। मुझे लगता है कि जब आपने 'संतुलित फ़ैसले' की बात की, तो आपने मेरे अगले सवाल का जवाब लगभग दे ही दिया था। लेकिन फिर भी, मैं वह सवाल पूछना चाहूँगा। आरबीआई ने हाल ही में अपना एक 'इनोवेशन हब' (नवाचार केंद्र) शुरू किया है, जिसका उद्घाटन गवर्नर साहब ने ही किया था। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मामले में आप केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका देखते हैं?

शक्तिकांत दास

इसकी भूमिका दोहरी है। पहली बात यह है कि हमारे मन में कुछ विचार और आइडिया हैं—खासतौर पर भुगतान के क्षेत्र और अन्य तरह की फिनटेक पहल से जुड़े हुए। हमारे पास एक 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' है, और कई ऐसे उत्पाद जो इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का हिस्सा थे। उनके ट्रायल पूरे हो चुके हैं, और हमने कह दिया है कि हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यह उन कंपनियों (खिलाड़ियों) पर निर्भर करता है कि वे उन्हें आगे कैसे बढ़ाती हैं।

एक तरफ, हमारी कुछ प्राथमिकताएँ हैं। हमें लगता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं—खास तौर पर भुगतान प्रणाली में— जहाँ हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिना इंटरनेट के भी, या फिर सबसे बेहतरीन तरीके से, हम अपने देश के पूरे भुगतान परिस्थितिकीतंत्र को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दूसरी तरफ, बहुत सारे नए नवाचार, नई पहल और स्टार्ट-अप सामने आ रहे हैं, जो नए और शानदार आइडिया लेकर आ रहे हैं। यह 'नवाचार केंद्र'— पहली बात— हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा; और दूसरी बात—यह आरबीआई को भी नए आइडिया सुझाएगा। तो, इसका पहला काम उन क्षेत्रों पर काम करने की कोशिश करना है। और दूसरा काम है—निजी क्षेत्र की पहल के साथ-साथ स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है, उनके साथ मिलकर काम करना और साझेदारी करना; उनके साथ मिलकर काम करना और उन्हें 'इन्क्यूबेशन सुविधाएँ' (शुरुआती मदद) देने की कोशिश करना, ताकि स्टार्ट-अप कंपनियाँ या स्टार्ट-अप उद्यमी अपने उत्पाद को बाज़ार में उतार सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने कई स्थानों पर अपने इनोवेशन हब स्थापित किए हैं। हमारे पास यह विकल्प था कि हम उनके किसी केंद्र को भारत में लाने की कोशिश करें, लेकिन हमने अपना खुद का केंद्र बनाने का फैसला किया; क्योंकि अगर हम अपना खुद का केंद्र बनाते हैं, तो हमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा यह कि हमारे पास पूरी आज़ादी होती है— हम जो चाहें, वह कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा यह कि बीआईएस जो कुछ भी कर रहा है, हम हमेशा उसका लाभ उठा सकते हैं—क्योंकि बीआईएस के इनोवेशन हब के साथ हमारा लगातार संवाद (बातचीत) चलता रहता है। यह एक ऐसी पहल है जिसे हमने आरबीआई की एक संस्था के तौर पर शुरू किया है, और इसका बोर्ड भी अब पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं लगातार इस पर नज़र रख रहा हूँ कि वहाँ क्या-कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि अब तक जो भी प्रगति हुई है, वह काफ़ी उम्मीद जगाने वाली है।

संजीव चड्ढा

धन्यवाद, गवर्नर साहब। मेरा आखिरी सवाल असल में उस विषय से जुड़ा है, जिसका उल्लेख आपने अपने संबोधन के आखिरी हिस्से में किया था— यानी बैंकिंग और 'कल के बाद' के बैंक। बैंक महामारी के दौर से ठीक-ठाक स्थिति में बाहर निकले हैं; ऐसे में रिज़र्व बैंक की शेष चिंताएँ क्या हो सकती हैं, और अगले कुछ वर्षों के लिए आरबीआई की कार्यसूची में कौन-से प्रमुख सुधार शामिल हो सकते हैं?

शक्तिकांत दास

लगातार सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पिछले तीन वर्षों में, महामारी, लॉकडाउन वगैरह के बावजूद, हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में गवर्नेंस से जुड़े कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं; हमने माइक्रोफाइनेंस लेंडिंग

के लिए एक नया विनियामकीय ढांचा, एनबीएफसी के लिए एक नया विनियामकीय ढांचा, और शहरी सहकारी बैंकों से जुड़ा एक नया विनियामकीय ढांचा प्रस्तुत किया है। इसलिए, हम लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक जोखिम प्रबंधन, अभिशासन, और समय की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ने की स्थिति में रहें। लेकिन हमारा इरादा किसी भी कमर्शियल गतिविधि में बिल्कुल भी दखल देना नहीं है। बैंक और उनकी टेक्नोलॉजी टीमों, उनकी कमर्शियल टीमों, और उनकी जोखिम प्रबंधन टीमों इन सभी मुद्दों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। एक विनियामक और पर्यवेक्षक के तौर पर, हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि कुल मिलाकर, वित्तीय स्थिरता बनी रहे। समय-समय पर वित्तीय स्थिरता के संबंध में नई चुनौतियाँ सामने आती रहती हैं। इसलिए, हमें अलग-अलग बैंकिंग संस्थाओं में हो रहे घटनाक्रमों पर, साथ ही पूरे इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इस पर पैनी नज़र रखनी होती है; और बैंकों के साथ मिलकर, उनके साथ साझेदारी में काम करना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हर समय मज़बूत बने रहें। महामारी के दौरान, हम बैंकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहते थे। लॉकडाउन के दौरान भी, हम पब्लिक और प्राइवेट, दोनों क्षेत्र के बैंकों के साथ वीडियो मीटिंग करते थे। एक बात जिस पर हम लगातार ज़ोर दे रहे थे, वह थी पूंजी जुटाना; क्योंकि हम जानते थे कि आगे चलकर, बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव पड़ सकता है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग हर बैंक ने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, और ज़्यादातर बैंकों ने पूंजी जुटाई। आज, हमारे पास एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र है, और बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। इसलिए, मूल विचार यह है कि बैंकों के साथ मिलकर लगातार काम किया जाए, खासकर उन चुनौतियों के संबंध में जो हमारे सामने अभी मौजूद हैं। इनमें से एक है पूरा डिजिटल और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, जहाँ बैंकों को भी समय की ज़रूरतों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा; साथ ही, बैंकों को नई संस्थाओं से भी चुनौती मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या हमें इन नई संस्थाओं को रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर हम उन्हें रेगुलेट करने का फैसला करते हैं, तो उन्हें किस तरह से रेगुलेट किया जाए। आगे क्या किया जाना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति किस तरह से बदलती है, और हम इस बदलती हुई स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है; आज की चुनौतियाँ बदलेंगी, और कल की चुनौतियाँ पूरी तरह से अलग होंगी। आने वाले कल से भी आगे की चुनौतियाँ कहीं ज़्यादा अलग होंगी। इसलिए, हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलना होगा।

संजीव चड्ढा

धन्यवाद, गवर्नर साहब। आप हमेशा की तरह बहुत ही दयालु, बेबाक और स्पष्टवादी रहे हैं। आपकी अनुमति से, चूंकि हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम दर्शकों से कुछ सवाल ले सकते हैं।

वाई. पितलवाला, बिज़नेस इंडिया

गवर्नर साहब, आपने वस्तुओं की कीमतों में महंगाई और युद्ध की वजह से पड़ने वाले उसके असर के बारे में बात की। भारत की जीडीपी और एक्सपोर्ट, दोनों में ही आयात का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि इन महंगाई की उम्मीदों को बढ़ाने में विनिमय दर का कितना हाथ है? क्योंकि यह भी इस बात में अहम भूमिका निभाएगा कि आप महंगाई की उन उम्मीदों को कैसे काबू में करते हैं।

शक्तिकांत दास

हम कच्चे तेल के बड़े इम्पोर्टर हैं। जब कच्चे तेल की कीमत 80-85 अमरीकी \$ प्रति बैरल से बढ़कर 120 अमरीकी \$ हो जाती है – असल में, यह 130 अमरीकी \$ प्रति बैरल तक पहुँच गई थी; आज, यह लगभग 106 अमरीकी \$ प्रति बैरल है – तो ज़ाहिर है, हम कच्चे तेल के उस बैरल के लिए ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। तो, जब आप आयात के लिए ज़्यादा कीमत चुकाते हैं, तो उसके दो कारण होते हैं: पहला, कीमतें बढ़ गई हैं; दूसरा, करेंसी की कीमत गिर रही है। इसे 'आयातित मुद्रास्फीति' (बाहर से आई महंगाई) कहते हैं। मौद्रिक नीति की कार्रवाई में भी महंगाई के इस आयातित हिस्से पर ध्यान दिया जाता है। हमारे सभी आकलन में, हमने मौजूदा साल के लिए औसत महंगाई का अनुमान 6.70 प्रतिशत रखा है। हम अगली एमपीसी बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है, और हम एमपीसी बैठक के दौरान इस पर चर्चा करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। ज़ाहिर है, यह एक ऐसा पहलू है जो हमारी महंगाई और हमारी कार्रवाई पर असर डालता है। मौद्रिक नीति की कार्रवाई में ज़ाहिर तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा, और रखा भी जाता है। वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, और साथ ही करेंसी की कीमत गिरने की वजह से कीमतों में और बढ़ोतरी – ये दोनों ही निश्चित रूप से अहम पहलू हैं। आयातित मुद्रास्फीति एक चुनौती है। आज, खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई भी, जैसा कि हमने पिछली नीतिगत बैठक में बताया था। हमारे पास गेहूँ का अतिरिक्त भंडार है, लेकिन गेहूँ की कीमतें इसलिए बढ़ गईं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गेहूँ की कीमतें बढ़ गई थीं; और इसका सीधा असर हमारी घरेलू महंगाई पर पड़ता है। हमारी महंगाई की गणना और अनुमान लगाते समय इन सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है।

वाई. पितलवाला, बिज़नेस इंडिया

आपने नेगेटिव इंटररेस्ट रेट्स के मुद्दे पर बात की और बताया कि इसका बचत और निवेश पर, और इसलिए ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। आपने यह भी बताया कि कोविड से पहले और कोविड के बाद भी हमारे यहाँ ऐसा ही था। मौजूदा अस्थिर हालात को देखते हुए, आप किस हद तक यह अनुमान लगाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत करने वालों के लिए नेगेटिव वास्तविक व्याज दरें बनी रहेंगी? खासकर जब हम ऐतिहासिक रूप से देखें, तो हम हमेशा से ही बचत पर ज़ोर देने वाली अर्थव्यवस्था रहे हैं, खासकर जब घरेलू क्षेत्र की बात आती है।

शक्तिकांत दास

ऋण वृद्धि के साथ-साथ बचत में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऋण वृद्धि अब 14 प्रतिशत तक पहुँच गई है। हमारे आधिकारिक आँकड़े, जो हमने हाल ही में जारी किए हैं, उनके अनुसार यह संख्या लगभग 13.5 या 13.4 प्रतिशत है, लेकिन यह पहले ही 14 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। जब क्रेडिट की माँग बढ़ती है, तो चलनिधि (नकदी) कम होती है, और संचलन में मौजूद करेंसी में बढ़ोतरी के कारण चलनिधि में हमेशा कुछ कमी आती

रहती है। हम अपनी नीतिगत दरें भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए, आगे चलकर, बैंकों ने अपनी परिसंपत्तियों की कीमतें करना शुरू कर दिया है। देयताएं पक्ष पर भी, कुछ बैंकों ने जमा दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। आगे चलकर, जब चलनिधि की ज़रूरत होगी, तो बैंक धीरे-धीरे और लगातार जमा दरें बढ़ाएंगे। जब हम नीतिगत दरें बढ़ाते हैं, तो उसका असर प्रणाली में देयता पक्ष पर मौजूद जमा दरों पर भी पड़ता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन आखिरकार, इसका असर जमा दरों पर भी ज़रूर पड़ेगा।

वीएमएल इंटीरियर प्रा. लिमि.

हाल ही में, आरबीआई ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटारा (सेटलमेंट) रूप में करने की अनुमति देने का फैसला किया है। तो, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या भारत की निर्भरता अमरीकी डालर पर बनी रहेगी, या यह भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करेगा?

शक्तिकांत दास

अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह एक अतिरिक्त सुविधा है जो हमने आयातकों और निर्यातकों को दी है। अब तक, जहाँ तक भारत का सवाल है, लगभग सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता रहा है। यह एक नई सुविधा है जिसे हमने शुरू किया है। उद्योग जगत की ओर से काफी समय से इसकी माँग की जा रही थी। इस विचार पर चर्चा चल रही थी और रिज़र्व बैंक में इसका मूल्यांकन किया जा रहा था। हम इस विचार पर काम कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य आयातकों और निर्यातकों को अपना व्यापार रूप में करने के लिए एक नया रास्ता, एक नया विकल्प उपलब्ध कराना था। इसके असर का अंदाज़ा लगाना अभी जल्दबाज़ी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ इसमें तेज़ी आएगी, पर हमें इंतज़ार करके देखना होगा। यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि भविष्य में यह कैसा रूप लेगा। लेकिन इसकी संभावनाएँ अच्छी हैं।

अरुंधति भट्टाचार्य

सुप्रभात, सर। सबसे पहले, आपके बहुत ही आश्वस्त करने वाले और ज्ञानवर्धक भाषण के लिए धन्यवाद। इस मंच से आपने जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर बहुत संतुष्टि मिली। मैं असल में जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछना चाहती थी; आपने इसका उल्लेख उन घटनाओं में से एक के तौर पर किया था, जिनका हम पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। भारत ने, कुल मिलाकर एक देश के तौर पर, अपने लिए 'नेट ज़ीरो' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) का लक्ष्य रखा है, जो कि काफी दूर का लक्ष्य है। आप अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। आप बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा) क्षेत्र के नियामक हैं। बीएफएसआई क्षेत्र से आगे चलकर कई ऐसे उद्योग जुड़े हैं, जो अभी 'नेट ज़ीरो' का दर्जा हासिल करने से काफी दूर हैं। हम यह भी जानते हैं कि भारत में 'जनादेश' सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। क्या एक नियामक के तौर पर, आपके मन में बीएफएसआई क्षेत्र के लिए 'नेट ज़ीरो' का दर्जा हासिल करने से जुड़ा कोई ऐसा जनादेश है?

शक्तिकांत दास

इस क्षेत्र में, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसे हम आपसी सहयोग से करना चाहेंगे। ठीक इसी उद्देश्य के साथ, हम जलवायु परिवर्तन और जलवायु से जुड़े जोखिमों पर एक 'चर्चा पत्र' जारी करने जा रहे हैं। यह चर्चा पत्र अगले हफ्ते के आस-पास जारी होने की उम्मीद है। यह एक चर्चा पत्र है, इसलिए हम सभी हितधारकों से सुझाव और विचार आमंत्रित करना चाहेंगे; और उन विचारों व इनपुट को प्राप्त करने के बाद, हम उनका आंतरिक रूप से मूल्यांकन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों की बात है, भारत ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सीओपी-26 के तहत भारत के लिए निर्धारित सभी लक्ष्य और पड़ाव हासिल कर लिए गए हैं। कई विकसित देशों ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन भारत ने सीओपी-26 के तहत अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। जी-20 के 'शेरपा' (प्रतिनिधि) के तौर पर काम करने के अनुभव के कारण, मैं इन क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों पर लगातार नज़र रखता हूँ। हमने अपने सभी जनादेश पूरे कर लिए हैं, और भारत का 'नेट ज़ीरो' का लक्ष्य है, जिसका ज़िक्र आपने भी किया है। हमें बहुत ही सोच-समझकर और संतुलित तरीके से आगे बढ़ना होगा। इसमें एक पहलू यह भी है कि विकास की गति को बहुत ज़्यादा धीमा न किया जाए, और दूसरा पहलू यह है कि लागत पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही, जलवायु से जुड़े जोखिमों को उचित और पर्याप्त प्राथमिकता देना भी ज़रूरी है। हमेशा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। जब हमारा चर्चा पत्र जारी होगा, तो मैं वरिष्ठ बैंकरों, अन्य हितधारकों, शिक्षाविदों, वित्त पेशेवरों और अन्य लोगों से उस पर उनके बहुमूल्य सुझावों और टिप्पणियों का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। हम बिना उचित परामर्श के बहुत ज़्यादा निर्देश देने वाले नहीं बनना चाहते। हमारा दृष्टिकोण परामर्श-आधारित रहा है; हम परामर्श करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।

अरुंधति भट्टाचार्य

आईटी उद्योग निश्चित रूप से योगदान दे सकती है। हम ऐसा करने के लिए तत्पर रहेंगे।

शक्तिकांत दास

अवश्य, बिल्कुल।

मोहित डेगन, मास्टरकार्ड

सुप्रभात, गवर्नर सर। मैं आपसे साइबर सुरक्षा के एक छात्र के तौर पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं साइबर सुरक्षा पर एक पाठ्यक्रम कर रहा हूँ। मैं उन चुनौतियों के बारे में पढ़ रहा हूँ जिनका सामना दुनिया भर के बैंक कर रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी आते हैं। तो, यह अवसरों के साथ भी उल्टा काम करता है, खासकर डिजिटल क्षेत्र में। कोविड और दूसरी टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल क्षेत्र में जो ज़बरदस्त उछाल आया है, उसे बैंकों ने अपनाया है। मेरा सवाल यह है कि क्या साइबरसुरक्षा के खतरे आपकी रातों की नींद उड़ा देते हैं? और अगर ऐसा है, तो बैंकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी?

शक्तिकांत दास

परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मेरी नींद कभी नहीं उड़ती। क्योंकि आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, आप हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसका सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए, आपको

अच्छी नींद लेनी चाहिए, ताकि आप मैदान में उतरकर अपनी बैटिंग कर सकें और अच्छी बैटिंग कर सकें। क्रिकेट पिच पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रात की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं क्रिकेट का फैन हूँ, इसलिए मैं हमेशा क्रिकेट से जुड़े उदाहरण ही देता हूँ।

अब, साइबर सुरक्षा एक असली समस्या है, यह एक असली खतरा है। जब कोविड महामारी शुरू हुई थी; तो मिस्टर चड्ढा और यहाँ मौजूद दूसरे वरिष्ठ बैंकों को याद होगा; 2020 में 28 फरवरी के आस-पास; हमने अंदरूनी तौर पर अपनी साइबर सतर्कता बढ़ा दी थी। हमने सभी बैंकों को केवल पत्र लिखकर ही जागरूक नहीं किया, बल्कि हमने सभी बैंकों के आईटी प्रमुखों के साथ बातचीत भी की। हमने बैंकों के सीईओ के साथ भी बैठक की, क्योंकि वह ऐसा समय था जब हमें उम्मीद थी कि साइबर हमलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ़ बैठे लोग यह सोचेंगे कि अब लोग कोविड पर ध्यान दे रहे हैं, और यह हमला करने का सबसे अच्छा समय है। इसलिए, सभी को जागरूक किया गया। यह एक चुनौती है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ मुझे लगता है कि हर बैंक, हर वित्तीय संस्थान—जिसमें रिज़र्व बैंक भी शामिल है—के आईटी सिस्टम को हमलावरों से एक कदम आगे रहना होगा। जिस तरह के साइबर हमले या कोई भी समस्या/खतरा सामने आ सकता है, उसके लिए जानकारी हासिल करना और लगातार सतर्क रहना ज़रूरी है। लोग एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में फैसला करना संस्थाओं का काम है, क्योंकि एथिकल हैकिंग के भी अपने नुकसान और जोखिम होते हैं। असल में, इसका मूल विचार यह है कि अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन करते रहें, अपने आस-पास होने वाली हर चीज़ की जानकारी रखें, और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के आईटी प्रणाली और आंतरिक कौशल में लगातार ज़्यादा निवेश करते रहें। आने वाले दिनों में, यह समस्या और भी बढ़ी होती जाएगी। इससे निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। हम किसी भी हाल में अपनी वित्तीय प्रणाली और हमारे पास मौजूद विशाल डेटा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते।

दीपांविता मजूमदार, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

सर, सिस्टम लेवल पर चलनिधि कम हुई है, और चलनिधि की स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन टिकाऊ चलनिधि अभी भी ऊँचे लेवल पर है और आगे चलकर दूसरी छमाही में जब करेंसी की माँग बढ़ेगी और आरबीआई का विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप काम होगा तो, इसका चलनिधि के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दरों पर क्या असर होगा?

शक्तिकांत दास

दरों पर क्या प्रभाव होगा, यह मैं नहीं कह सकता। आपको मौद्रिक नीति समिति की बैठकों का इंतज़ार करना होगा। दरें, बदलती हुई महंगाई और विकास की स्थितियों पर निर्भर करेंगे। जहाँ तक चलनिधि की बात है, आज अगर आप 14 दिन के वीआरआरआर, 28 दिन के वीआरआरआर, और एसडीएफ के ज़रिए हमारे पास वापस आने वाली चलनिधि को मिला दें, तो यह लगभग 2.8-2.9 लाख करोड़ रुपये बैठता है। सरकार का नकदी शेष भी है। इन सबको मिलाकर, सिस्टम में हमारे पास लगभग 5.0-6.0 लाख करोड़ रुपये की चलनिधि है। तो, चलनिधि अभी भी बहुत सहज स्थिति में है। हाँ, आप सही कह रही हैं; आगे चलकर, जैसे-जैसे क्रेडिट ऑफ़टेक बढ़ेगा, जैसे-जैसे दूसरी तिमाही से और मॉनसून के बाद सरकारी खर्च बढ़ेगा; और आपने विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप का भी उल्लेख किया, जो रिज़र्व बैंक समय-समय पर करता रहता है; चलनिधि का स्तर नीचे आएगा।

लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम यह पक्का करेंगे कि अर्थव्यवस्था की क्रेडिट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टम में हमेशा पर्याप्त चलनिधि बनी रहे। इससे ज़्यादा, मैं यह नहीं कह पाऊँगा कि हम कितनी चलनिधि के साथ सहज हैं। हम यह पक्का करेंगे कि क्रेडिट ऑफ़टेक की अनदेखी न हो, और चलनिधि की समस्याओं की वजह से क्रेडिट ऑफ़टेक पर कोई बुरा असर न पड़े। तो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति किस तरह से बदलती है।

संजीव चड्ढा

बहुत-बहुत धन्यवाद, गवर्नर साहब, कि आपने इतने सारे सवालों के जवाब इतनी शांति से दिए।